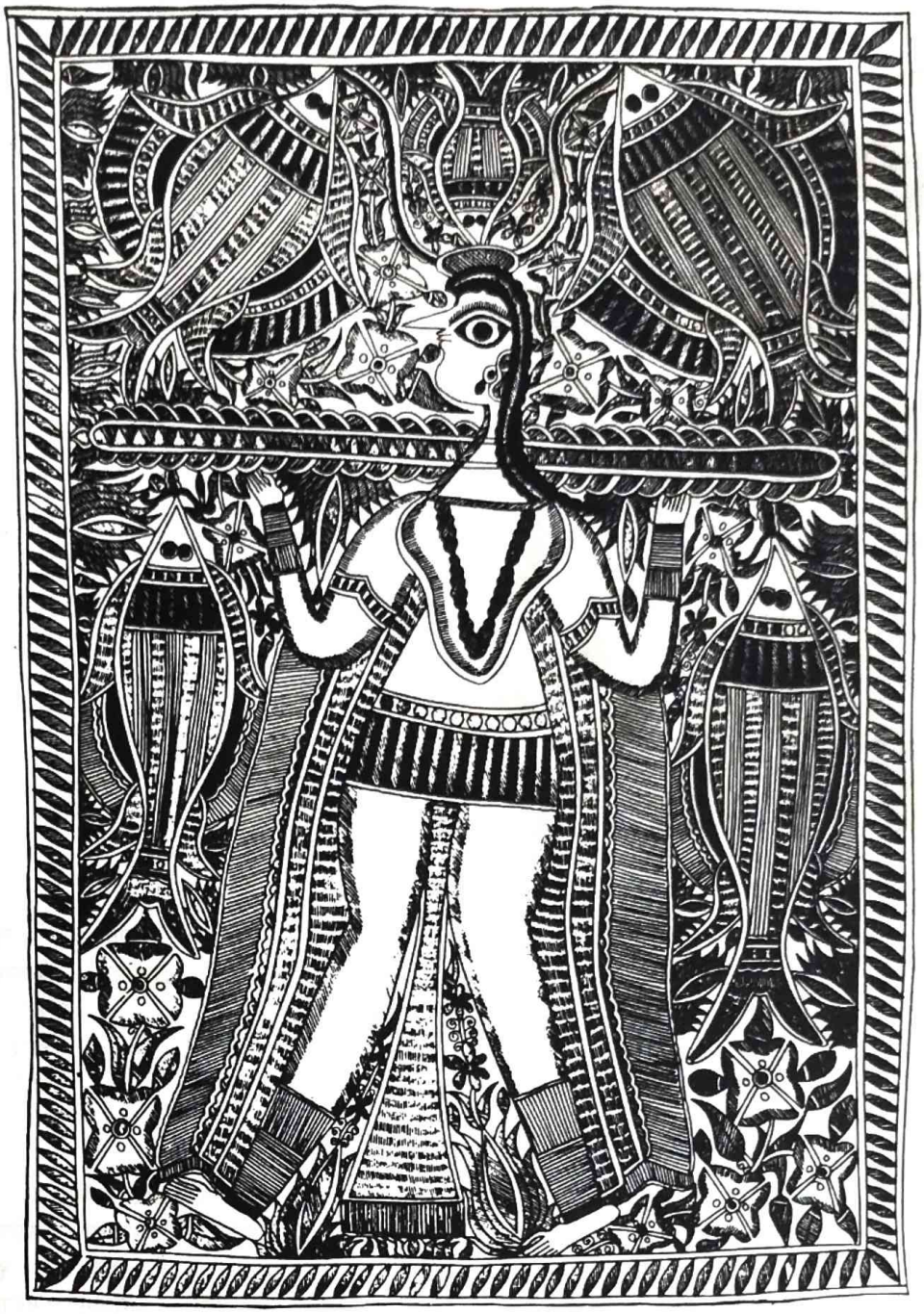

औरतों की स्थिति में देशों का क्रम :

ग़रीब, निर्बल और गर्भवती

अनुवाद : डॉ. सुशील जोशी
प्रकाशक : किशोर भारती
पोस्ट बनखेड़ी
जिला होशंगाबाद
पिन 461990

यह पुस्तिका किशोर भारती के प्रजनन जागरूकता कार्यक्रम के तहत प्रकाशित की गई है। इस कार्यक्रम के लिए अनुदान सहायता मानव संसाधन विकास मंत्रालय (भा. स.) से मिली ।

अनुपम मुद्रण द्वारा मुद्रित

गरीब, अधिकारों से वंचित और गर्भवतीः

महिलाओं के हालात के मुताबिक देशों का क्रम

(1988)

Country Rankings of the Status of Women:
Poor, Powerless and Pregnant, 1988

(ISSN 0197-2235 BP-20);
Population Crisis Committee;
1120 19th Street. N W
Washington, D C 20036 (USA)

का संक्षिप्त हिंदी स्वरूप

अनुवाद

डॉ. सुशील जोशी

किशोर भारती

1989

गरीब, अधिकारों से वंचित और गर्भवती: महिलाओं के हालात के मुताबिक देशों का क्रम (1988)

यह पुस्तिका किशोर भारती के 'प्रजनन जागरूकता कार्यक्रम' - के तहत सन् 1989 में प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (भारत सरकार) से अनुदान प्राप्त हुआ।

आवरण : डॉ. कैरन हेडॉक

पहला संस्करण : जनवरी 1989 (500प्रतियां)

किशोर भारती के **'प्रजनन जागरूकता कार्यक्रम'** के तहत यह पुस्तिका संदर्भ सामग्री बतौर **सहभागियों को नि:शुल्क उपलब्ध** कराई गईं।

प्रकाशक : किशोर भारती

इस पुस्तिका में छपी किसी भी सामग्री का उपयोग, उद्धरित एवं पुनर्प्रकाशन करने की पूरी छूट है। अपेक्षा केवल यह है कि ऐसा करते समय चयनित सामग्री के स्रोत का पृष्ठ संख्या सहित पूरा ज़िक्र किया जाए।

दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में औरतों की स्थिति में बहुत भिन्नता है। कहीं भी औरतें आदमियों के बराबर दर्जे की हकदार नहीं हैं। परंतु अफ्रीका, मध्य पूर्व व दक्षिण एशिया और लैटिन अमरीका में गरीबी के साथ-साथ लंबे समय से चले आ रहे स्त्री-पुरुष भेदभाव के कारण औरतों की जिन्दगी के हालात इतने निर्मम हैं कि पश्चिमी औद्योगिक देशों की औरतों के लिए उनकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है।

दुनिया की निर्धनतम औरतें मात्र निर्धन ही नहीं हैं, बल्कि मात्र ज़िन्दा रहने की कगार पर हैं। वे आर्थिक रूप से निर्भर हैं और आसानी से चोट खा सकती हैं, एवं राजनैतिक व कानूनी रूप से शक्तिहीन हैं। पत्नियों और मांओं के रूप में वे एक ऐसे जीवनचक्र में फंसी हैं जो कम उम्र में शादी से शुरू होकर कई बार जचकी के दौरान मौत में खत्म हो जाता है। वे मर्दों के मुकाबले ज़्यादा समय और कई बार ज़्यादा कठोर परिश्रम करती हैं, परंतु आमतौर पर उनका काम अवैतनिक होता है और उसकी कीमत भी कम आंकी जाती है।

दुनिया भर में औरतें दुनिया के कुल खाद्यान्न का लगभग आधा हिस्सा पैदा करती हैं किन्तु अधिकांश औरतें ज़मीन की मालिक नहीं हैं। सवैतनिक कामगारों की संख्या का एक तिहाई हिस्सा औरतें हैं परंतु वे सबसे कम वेतन वाले कामों में लगी हुई हैं। सरकारी संस्थाओं में उनका प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है। यदि वे घर के बाहर काम करती हैं, तो अधिकांश दोहरा बोझ वहन करती हैं; परिवार की आय में अपने योगदान के बावजूद बच्चों की देखभाल और घरेलू कामकाज की पूरी जिम्मेदारी उनकी ही होती है।

इस अध्ययन में 99 देशों की 2 अरब 30 करोड़ दुनिया की औरतों की संख्या का 92 प्रतिशत के हालातों को 20 सूचकों की मदद से आंका गया है। ये सूचक पांच क्षेत्रों से संबंधित हैः स्वास्थ्य, शादी और बच्चे, शिक्षा, रोज़गार और सामाजिक समानता। हर क्षेत्र में तीन सूचक देशों के बीच औरतों की स्थिति की तुलना करते हैं। उदाहरण के लिए स्कूल में लड़कियों का प्रतिशत। चौथा सूचक एक ही देश में लिंगों के बीच की खाई का मापन करता है। उदाहरण के लिए मर्द और औरत की साक्षरता दर।

इन बीस सूचकों के मूल आंकड़े मानक आंकड़ों से इकट्ठा किए गए और फिर इन्हें 5 बिन्दु वाले एक पैमाने में बदला गया। इस प्रकार से हर क्षेत्र में अधिकतम स्कोर 20 और कुल अधिकतम स्कोर 100 हो सकता है। सभी 99 देशों के लिए 20 सूचकों के आंकड़े साथ के पोस्टर में दिए गए हैं।

संभावित अंकों को उत्तम से निकृष्ट तक की सात श्रेणियों में बांटा गया। हालांकि किसी एक क्षेत्र में कुछ देशों का स्कोर उत्तम की श्रेणी में आता है, परंतु किसी भी देश का कुल स्कोर उत्तम श्रेणी (100 में से 90 अंक) में नहींआया। केवल सात देशों का स्कोर 80 या उससे ज़्यादा है जिसके आधार पर इन्हें "बहुत अच्छा" की श्रेणी में रखा गया। स्वीडन (87) का स्कोर अधिकतम और बंगलादेश (21.5) का स्कोर न्यूनतम रहा।

देशों के क्रम के अनुसार औरतों का वितरण

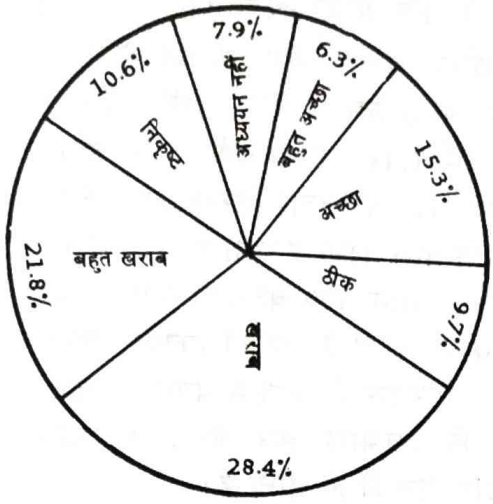

देशों की श्रेणी	0-100 अंक		
श्रेष्ठ	90-100	खराब	50-59.5
बहुत अच्छा	80-89.5	बहुत खराब	40-49.5
अच्छा	70-79.5	निकृष्ट	39.5 से कम
ठीक	60-69.5	अध्ययन नहीं	

अध्ययन में शामिल 99 में से 51 देश सबसे निचली तीन श्रेणियों में आए:- खराब, बहुत खराब और निकृष्ट। इन श्रेणियों के स्कोर 59.5 से 21.5 के बीच हैं। अध्ययन से आभास मिला है कि दुनिया की 60 प्रतिशत औरतें और लड़कियां ऐसे हालातों में जी रही हैं जिनमें उनके स्वास्थ्य को खतरा है, उन्हें बच्चे पैदा करने संबंधी निर्णय से वंचित किया गया है, शैक्षिक उपलब्धि सीमित कर दी गई है, आर्थिक भागीदारी पर बंधन है और आदमियों के समान अधिकार व आज़ादी की गारन्टी नहीं है।

यह कोई अचरज की बात नहीं है कि उत्तरी अमरीका और उत्तरी यूरोप के देश ऊंची श्रेणियों में बहुतायत से हैं और अफ्रीका, मध्यपूर्व व दक्षिण एशिया के देश निचली श्रेणियों में। परंतु कुछ दिलचस्प अपवाद भी हैं।

स्विट्ज़रलैंड (जहां औरतों को मताधिकार 1971 में जाकर मिला) का स्कोर 73 है और यह 24 वें स्थान पर है। खाड़ी के तेल निर्यात करने वाले व उच्च आय वाले देशों का स्कोर 50 से कम रहा और ये बहुत खराब और निकृष्ट की श्रेणी में आए। ज़्यादा आश्चर्य की बात है कि दक्षिण अमरीका के कुछ उच्च मध्यम आय वाले देश भी अपेक्षाकृत निचली श्रेणियों में हैं। जैसे ब्राज़ील का स्कोर मात्र 54.5 है। इसके विपरीत कुछ निम्न आय वाले देश जैसे श्रीलंका और चीन के स्कोर काफी अच्छे हैं (क्रमशः 60 और 58.5)।

अध्ययन से इन पांच क्षेत्रों में औरतों के हालात के महत्वपूर्ण संबंधों की पुष्टि होती है। उदाहरण के लिए, शैक्षिक उपलब्धि का संबंध मात्र रोजगार से नहीं बल्कि स्वास्थ्य, परिवार के आकार और विवाह में समानता से भी है। शादी और बच्चे पैदा करने के तौर तरीकों का असर औरतों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति पर होता है। जिन औरतों को शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में ज़्यादा अवसर हैं वे देर से शादी करती हैं और लगभग मनचाही संख्या के बच्चों को जन्म देती हैं। दूसरी ओर, जिन औरतों की शादी जल्दी हो जाती है, और जो बार-बार गर्भवती होती हैं, वे अपने देश में उपलब्ध शिक्षा व सवैतनिक रोज़गार के न्यूनाधिक अवसरों से वंचित रह जाती हैं।

यदि औरतों को अपने देश के सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक विकास में आदमियों के साथ पूरी भागीदारी करना है, तो उन्हें पुराने समय से चले आ रहे भेदभाव के तौर तरीकों को बदलना होगा- जो कि प्रत्येक देश में किसी न किसी हद तक मौजूद हैं- जिनके कारण वे दूसरे दर्जे की नागरिक बनी रहती हैं। उन्हें अपने जीवन के उस हिस्से पर भी नियंत्रण स्थापित करना होगा जो सामान्य रूप से औरतों के जीवन और मर्दों के जीवन में अंतर करता है। उन्हें यह निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए कि बच्चा चाहिए या नहीं, और यदि चाहिए, तो कब? उन्हें बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी में पति, नियोक्ता और सरकार को भी शामिल करना होगा। कुछ औद्योगिक देशों के संभावित अपवाद के अलावा दुनिया के किसी भी हिस्से में ऐसी मदद बहुत कम मिल पाती है। और दुनिया की आधी औरतों को बच्चा जनने संबंधी वास्तविक निर्णय का अधिकार नहीं है।

स्वास्थ्य

जीवन स्तर, खासकर पोषण स्थिति और चिकित्सा सुविधाओं, में बहुत ज़्यादा अंतरों के कारण दुनिया के सबसे अमीर देशों में (मर्द-औरत दोनों की) प्रत्याशित आयु दुनिया के निर्धनतम देशों की तुलना में दुगनी है। इनके आंकड़े 80 साल की तुलना में 45 साल है। अधिकांशतः अंतरों को निर्धन देशों में ऊंची शिशु मृत्यु दर के आधार पर समझा जा सकता है। दुनिया के अधिकांश हिस्से में औरतों की औसत प्रत्याशित आयु आदमियों से ज़्यादा है। परंतु औरत और आदमी की प्रत्याशित आयु में यह अंतर गरीब देशों में कम है और कहीं-कहीं तो सामान्य से उल्टा भी है। यानि आदमियों की प्रत्याशित आय औरतों से ज़्यादा है। सांख्यिकी की ऐसी गड़बड़ियों से भेदभाव की व्यवस्था का संकेत मिलता है जिसमें कम उम्र में लड़कों को लड़कियों की तुलना में ज़्यादा तरज़ीह दी जाती है। इनसे गरीब देशों में मातृत्व संबंधी मृत्यु की ऊंची दर का भी आभास मिलता है। (गर्भ, जचकी या गैर-कानूनी गर्भपात के कारण मौतें)।

इस अध्ययन में देशों के बीच तुलना के लिए तीन सूचकों और एक ही देश में लिंगों के बीच तुलना के लिए एक सूचक का उपयोग किया गया। आंकड़ों का प्रमुख स्रोत यू.एस. ब्यूरो ऑफ सेंसस (अमरीकी जनगणनाब्यूरो) का अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ा संकलन था।

* **मादा शिशु-व-बाल मृत्यु दरः** तकनीकी रूप से मादा शिशु-व-बाल मृत्यु दर कुल पैदा होने वाली लड़कियों में से उन लड़कियों का प्रतिशत है जो पांचवीं वर्षगांठ से पहले ही मर जाती हैं।

* **महिला मृत्यु दर-बच्चे पैदा कर पाने वाली अवधिः** 15 साल उम्र की औरतों में से उन औरतों का प्रतिशत जो 45 वर्ष की उम्र से पहले ही मर जाएंगी। इस जानकारी का आधार औरतों की वर्तमान उम्र की विशेष मृत्यु दरें हैं।

स्वास्थ्य

स्कोर	देश
20.0	फिनलैंड
19.5	ऑस्ट्रिया, फ्रांस
19.0	ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, प. जर्मनी, हंगरी, इटली, नीदरलैंड, नार्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, संयुक्त राज्य
18.5	बुल्गारिया, चीले, कोस्तारिका, चेकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, ग्रीस, हाँगकाँग, आयरलैंड, जापान, न्यूज़ीलैंड, स्पेन, युनाइटेड किंगडम
18.0	पू. जर्मनी, सिंगापुर, उरुगुए, सोवियत संघ, यूगोस्लाविया
17.5	आर्जेन्तीना, बारबेदोस, इज़राइल, जमैका, द. कोरिया, रुमानिया, ताइवान
17.0	पनामा
16.5	कुवैत, मलेशिया, मेक्सिको, त्रिनीदाद एंड तोबागो, वेनेसुएला
16.0	क्यूबा, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात
15.5	गुआना, पारागुए, फिलिपीन्स, थाइलैंड, तुनीसिया
15.0	ब्रासील, कोलंबिया, एक्वदोर, जॉर्डन, लिबिया
14.5	द. अफ्रीका
14.0	आल्जीरिया, चीन, सिरिया
13.5	दोमिनिकन रिपब्लिक, होन्दूरस, साउदी अरब, तुर्की
13.0	बोत्स्वाना, गुआतेमाला, कीन्या, मोरॉको, पेरु, ज़िम्बाब्वे
12.5	एल सल्वादोर
12.0	ईराक, लेसोतो
11.5	इंदोनेशिया
10.5	मिस्र, भारत, निकारागुआ
10.0	बोलिविया, सूदान, ज़ाम्बिया
9.5	लाईबीरिया, तन्ज़ानिया
9.0	हैती, सेनेगल
8.5	कैमारून
8.0	बेनिन, पाकिस्तान, रुआण्डा
7.0	मलावी
6.5	मोज़ाम्बीक
6.0	नाईजीरिया, उ. यमन
5.5	बंगलादेश, माली
3.5	अफगानिस्तान

उच्चतम व न्यूनतम कोटि के देशों में औरतों की स्थिति

स्वीडन	बांगलादेश
(जनसंख्या 84 लाख, क्षेत्रफल 173,730 वर्ग मील)	(जनसंख्या 11 करोड़, क्षेत्रफल 55,598 वर्ग मील)
■ स्त्री की प्रत्याशित आयु 81 वर्ष है।	■ स्त्री की प्रत्याशित आयु 49 वर्ष है।
■ 167 में 1 लड़की पांचवीं वर्षगांठ से पहले मर जाती है।	■ 5 में 1 लड़की पांचवीं वर्षगांठ से पहले मर जाती है।
■ 15 वर्ष की 53 औरतों में से 1 बच्चा जनने की उम्र में मर जाती है (इनमें से एक प्रतिशत मौतें गर्भ या जचकी से जुड़ी होती हैं)।	■ 15 वर्ष की 6 औरतों में से 1 बच्चा जनने की उम्र में मर जाती हैं (इनमें से करीब एक-तिहाई मौतें गर्भ और जचकी से संबंधित होती हैं)।
■ 15-19 वर्ष की औरतों में से 1 प्रतिशत से कम शादीशुदा होती हैं।	■ 15-19 वर्ष की औरतों में से करीब 70 प्रतिशत शादीशुदा होती हैं।
■ एक औरत औसतन 1-2 बच्चे जनती है।	■ एक औरत औसतन 5-6 बच्चे जनती है।
■ तीन-चौथाई से ज्यादा शादीशुदा औरतें गर्भनिरोधक उपयोग करती हैं।	■ एक-चौथाई शादीशुदा औरतें गर्भनिरोधक उपयोग करती हैं।
■ स्कूली उम्र की लगभग सारी लड़कियां स्कूल में दाखिल हैं।	■ स्कूली उम्र की 3 लड़कियों में से 1 ही स्कूल में दाखिल है।
■ औरतों का वि.वि. में दाखिला 20-24 वर्ष की कुल औरतों का 37 प्रतिशत है।	■ औरतों की वि.वि. में दर्ज संख्या 20-24 वर्ष की कुल औरतों का 2 प्रतिशत से कम है।
■ माध्यमिक स्कूलों की आधे शिक्षक औरतें हैं।	■ दस माध्यमिक स्कूल शिक्षकों में से एक औरत है।
■ पांच में से 3 औरतें सवैतनिक श्रम शक्ति में शामिल हैं।	■ 15 में से 1 औरत ही सवैतनिक श्रम शक्ति में शामिल है।
■ पांच में से दो औरतें व्यवसायिक हैं।	■ 1000 में से मात्र 3 औरतें व्यवसायिक हैं।
■ औरतें औसतन आदमियों से सात साल ज्यादा जीती हैं।	■ औरतें औसतन आदमियों से दो साल कम जीती हैं।
■ आदमी-औरत की साक्षरता दर समान है।	■ आदमियों से 24 प्रतिशत ज्यादा औरतें निरक्षर हैं।
■ सवैतनिक कामगारों में से आधी औरतें हैं।	■ सवैतनिक कामगारों में औरतों का प्रतिशत 14 है।
■ 1988 में स्वीडन की 349 सदस्यीय संसद में 113 सीटों पर औरतें थीं।	■ 1988 में बांगलादेश की 302 सदस्यीय संसद की 30 आरक्षित सीटों में से मात्र 4 सीटें औरतों के पास थीं।

* **जन्म के समय लड़कियों की प्रत्याशित आयु:** जन्म के समय एक औरत औसत कितने साल जीने की उम्मीद करती है।

* **लिंग अंतर: लड़कियों/लड़कों की भिन्न प्रत्याशित आयु:** लड़की और लड़के की जन्म समय प्रत्याशित आयु में अंतर। बहुत थोड़े अंतर या लड़के की प्रत्याशित आयु ज़्यादा होना स्वास्थ्य की स्थिति में लिंग का अंतर दिखाता है।

मादा शिशु-व-बाल मृत्यु दर

अध्ययन से पता चलता है कि पूर्वी यूरोप को छोड़कर बाकी सारे औद्योगिक देशों में प्रति 100 में से 99 लड़कियां पहले पांच साल तक ज़िन्दा रहेंगी। हांगकांग, इज़राइल, सिंगापुर, ग्रीस और कोस्टारिका भी इसी श्रेणी में आते हैं।

इसके विपरीत अफगानिस्तान, बंगलादेश, माली, उत्तरी यमन और पाकिस्तान में 100 में से 80 लड़कियां ही पांच साल की उम्र तक जीवित रह पाती हैं। अध्ययन में शामिल देशों में से एक-तिहाई ऐसे हैं जिनमें 100 में से 90 से कम लड़कियां 5 वर्ष तक पहुंचती हैं। इन देशों में नर शिशु-व-बाल मृत्यु-दर भी ऊंची है।

प्रतिवर्ष पांच साल से कम उम्र में मरने वाले डेढ़ करोड़ बच्चों में से अधिकांश को आसान चिकित्सा और रोकथाम के उपायों से बचाया जा सकता है, जैसे, पोषण की निगरानी, टीके लगाना, बेहतर स्वच्छता, साफ पीने का पानी और बच्चों के जन्म के बीच के अंतर को बढ़ाकर।

बच्चों के स्वास्थ्य और बच्चियों को मिलने वाली देखभाल की मात्रा पर भी परिवार के आकार का असर पड़ सकता है। सारे देशों में मां, एक महत्वपूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्यदाता है। जिन परिवारों में लड़के को प्राथमिकता है वहां मां के पास उपलब्ध थोड़े से समय के लिए प्रतियोगिता में लड़की हार जाएगी। हो सकता है कि उन्हें भोजन भी कम मिले। बहुत सारे देशों में पुरुष और लड़के पहले खाते हैं; औरतें और लड़कियां बचा-खुचा खाती हैं। गरीब परिवारों में यह बहुत ही कम हो सकता है। इन तौर-तरीकों का आभास कई विकासशील देशों में आदमी-औरत की प्रत्याशित आयु की भिन्नता में परिलक्षित होता है।

बच्चे जनने की उम्र में औरतों की मृत्यु दर

दुनिया के निर्धनतम देशों में गर्भावस्था, गर्भपात या जचकी की जटिलताओं के परिणामस्वरूप औरतों के मरने की संभावना अमीर देशों के मुकाबले 200 गुना ज़्यादा है। चूंकि गरीब देशों में औरतें ज़्यादा गर्भवती होती हैं इसलिए बच्चे जनने की उम्र में मौतों का एक बड़ा कारण मातृत्व से जुड़ी मौतें होना है। संपन्न देशों में निरापद गर्भपात और जच्चा की देखभाल की अच्छी सुविधाओं की वजह से मातृत्व से जुड़ी मौत एक बिरली बात हो गई है। परंतु फिर भी पूरी दुनिया में प्रतिवर्ष पांच लाख से ज़्यादा औरतें प्रजनन स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण मरती हैं। मौत की शिकार प्रत्येक औरत के साथ-साथ दस-पंद्रह अपंग हो जाती हैं। कोई दो करोड़ पचास लाख औरतें जचकी के दौरान गंभीर जटिलताओं जैसे रक्त स्राव या संक्रमण से ग्रस्त होती हैं।

अध्ययन में शामिल 99 देशों में से एक चौथाई में

हर 10 औरतों में से एक 15 से 45 वर्ष की उम्र में मौत की शिकार हो जाती हैं। अफगानिस्तान, बेनिन, कैमरून, मलावी, माली, मोज़ाम्बिक, नेपाल, नाइजीरिया और उत्तरी यमन में यह संख्या पांच में से एक की है। जिन देशों में वयस्क औरत मृत्युदर न्यूनतम है वहां 100 में से मात्र एक औरत बच्चे जनने की उम्र में मरती है।

लिंग अंतर: महिला और पुरुष की प्रत्याशित आयु

स्विट्ज़रलैंड में जन्म के समय औरत की औसत प्रत्याशित आयु 82 वर्ष है; कनाडा, हांगकांग, इटली, जापान, नीदरलैंड, नार्वे और स्वीडन में कम से कम 80 वर्ष है। दूसरे छोर पर अफगानिस्तान में औरत की औसत प्रत्याशित आयु 41 वर्ष और बंगलादेश, मलावी, माली, मोज़ाम्बिक, नेपाल, नाइजीरिया और उत्तरी यमन में 50 से कम है।

निम्न आय वाले देशों में पुरुषों की प्रत्याशित आयु भी कम होती है पर विश्व में महिला और पुरुषों की प्रत्याशित आयु में अंतर बदलता रहता है। अधिकांश औद्योगिक देशों में औरतों की प्रत्याशित आयु पुरुषों के मुकाबले औसतन 7 वर्ष ज़्यादा है परंतु अधिकांश विकासशील देशों में यह अंतर घटकर 2 वर्ष रह जाता है और सबसे कम अंतर वाले देश हैं पाकिस्तान, भारत, मिस्र, हइटी और इराक। बंगलादेश और नेपाल में आदमियों की प्रत्याशित आयु औरतों से ज़्यादा है। ये आंकड़े कुछ मामलों में उस भेदभाव को दिखाते हैं जिसके चलते लड़कियों की उपेक्षा की जाती है। कुछ दक्षिण एशियाई देशों में लड़के को इतनी ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है कि कन्या शिशु-व-बाल मृत्यु की ऊंची दर मध्यम व उच्च आय वर्ग में भी पाई जाती है।

शादी और बच्चे

स्कोर	देश
20.0	ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड
19.5	स्वीडन, ताइवान
19.0	बेल्जियम, फिनलैंड, नीदरलैंड, नार्वे, यूनाइटड, किंगडम
18.5	कनाडा, चीन, चकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, फ्रांस, पू. जर्मनी, प. जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, संयुक्त राज्य
18.0	ऑस्ट्रीया, हाँगकाँग, हंगरी, इटली, उरुगुए, सोवियत संघ
17.5	आयरलैंड, इज़राइल, सिंगापुर
17.0	बुल्गारिया, क्यूबा, जापान, पोलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, यूगोस्लाविया
16.5	आर्जेन्तीना, कोस्तारिका, पनामा, रुमानिया
16.0	बारबेदोस, चीले, ग्रीस, जमैका, थाइलैंड, त्रिनीदाद एंड तोबागो
15.5	कोलंबिया, गुआना, द. कोरिया, श्रीलंका
15.0	ब्रासील, दोमिनिकन रिपब्लिक, मलेशिया
14.5	फिलिपीन्स, तुर्की
14.0	मेक्सिको, पेरु, द. अफ्रीका
13.5	एल सल्वादोर, वेनेसुएला
13.0	एक्वादोर, परागुए, तुनीसिया
12.0	भारत
11.5	बोलिविया, बोत्स्वाना, इंदोनेशिया
11.0	गुआतेमाला, हैती, होन्दूरस, मोरॉको, पाकिस्तान
10.5	मोज़ाम्बीक, निकारागुआ, ज़िम्बाब्वे
10.0	मिस्र, कुवैत
9.5	आल्जीरिया, लिबिया, रुआण्डा, संयुक्त अरब अमीरात
9.0	लाईबीरिया, नेपाल
8.5	ईराक, लेसोतो, सिरिया, तन्ज़ानिया, ज़ाम्बिया
8.0	कैमरून, जॉर्डन, कीन्या, सेनेगल
7.05	सूदान, उ. यमन
.0	अफगानिस्तान
6.5	बेनिन, मलावी
5.5	माली, नाईजीरिया
4.5	बंगलादेश
4.0	साउदी अरब

शादी और बच्चे

उनकी कुछ भी आकांक्षाएं हों या वे कुछ भी बनना चाहती हों पर दुनिया की अधिकांश औरतें पत्नियां और मांएं बन जाती हैं। जिस उम्र में औरतें शादी करती हैं और बच्चे जनना शुरू करती हैं, बच्चों की संख्या और गर्भनिरोध साधनों के जरिए गर्भ के समय का नियंत्रण की क्षमता आदि सभी का असर औरत के सामाजिक दर्जे, स्वास्थ्य और आर्थिक हालातों पर पड़ता है। इनमें से अधिकांश संबंध एक-दूसरे को पुख्ता बनाते हैं।

इस अध्ययन में शादी और जचकी के क्षेत्र में औरतों की स्थिति को मापने के लिए चार कारकों का इस्तेमाल किया गया। आंकड़ों के प्रमुख स्रोत हैं: यू.एस. ब्यूरो आफ सेन्सस, राष्ट्रसंघ सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्र संघ जनसंख्या विभाग और जनसंख्या परिषद्।

* **किशोर विवाह-** 15 से 19 वर्ष की उम्र में शादीशुदा औरतों का प्रतिशत है।

* **कुल प्रजनन दर-** एक औरत अपनी ज़िन्दगी में औसत जितने बच्चे जनेगी। यह वर्तमान आयु-विशेष उर्वरता दरों पर आधारित है।

* **गर्भनिरोध प्रचलन-** विवाहित या जोड़े में रह रही औरतों में से उन औरतों का प्रतिशत जो गर्भनिरोध का उपयोग करती हैं (इसमें पारंपरिक साधन/विधियां शामिल हैं)।

* **लिंगों में अंतर- विधवा, तलाकशुदा या अलग अलग-** इसका मतलब विधवा, तलाकशुदा और अलग रहने वाली औरतों और विधुर, तलाकशुदा और अलग रहने वाले आदमियों के अनुपात से है। हरेक देश में जिन परिवारों में औरतें खुद की या परिवार की अकेली सहारा हैं वे परिवार सामाजिक-आर्थिक सीढ़ी की सबसे निचली पायदान पर होते हैं।

जल्दी शादी और बच्चे जनना

डेनमार्क, जापान और स्वीडन में 100 में से मात्र 1 औरत 20 वर्ष की उम्र से पहले शादी करती है। इन देशों और अन्य औद्योगिक देशों में अधिकांश औरतें शादी से पहले सेकण्डरी स्कूल पूरा कर लेती हैं और औरतों का काफी बड़ा हिस्सा विश्वविद्यालय के चार वर्ष भी पूरे कर लेता है।

विकासशील देशों में शादी और बच्चे जनने का तौर तरीका बिलकुल ही अलग है। बंगलादेश में 19 साल से कम उम्र की लड़कियों में से दो तिहाई शादीशुदा होती हैं और अफगानिस्तान, मलावी, माली, नेपाल, उत्तरी यमन और संयुक्त अरब अमीरात में आधी से ज़्यादा लड़कियां शादीशुदा होती हैं। इनमें से कई की तो रजस्वला होने के तुरंत बाद शादी हो जाती है। मध्यपूर्व व दक्षिण एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में अक्सर

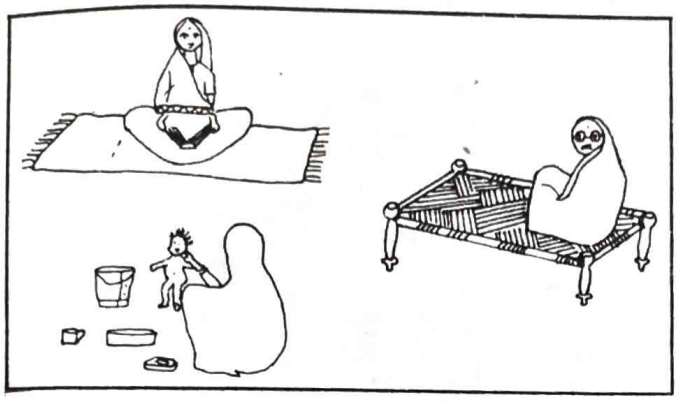

किशोर लड़कियों और काफी बड़े पुरुषों के बीच शादियां तय की जाती हैं। प्रतिष्ठा में गैर बराबरी, प्रभावशीलता और स्वायत्तता पत्नी और पति के बीच के उम्र के अंतर बढ़ने के साथ-साथ बढ़ती है। जिन देशों में एक तिहाई या उससे भी ज़्यादा औरतों की शादी किशोरावस्था में हो जाती है, वहां औरतों की कुल मिलाकर स्थिति अंतिम दो श्रेणियों (बहुत खराब या निकृष्ट) में ही आती है।

विकसित और विकासशील दोनों देशों में जल्दी बच्चे जनने के कारण स्वास्थ्य जटिलताओं की संभावना बढ़ जाती है। किशोर मांओं में 20 वर्ष से ऊपर उम्र की मांओं की तुलना में मौत का जोखिम दुगना होता है। विकसित और विकासशील दोनों देशों में बहुत ज़्यादा औरतें बहुत जल्दी मां बन जाती हैं, जिससे उनके और बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

बच्चों की संख्या और गर्भनिरोध का उपयोग

जल्दी शादी और बच्चे जनने का ऊंची प्रजनन दर से निकट का रिश्ता है। जिन देशों में 15 से 19 वर्ष की लड़कियों की शादी कर दी जाती है, वहां औरतें औसतन 6 या 7 बच्चे जनती हैं। यह देर से शादी वाले देशों की तुलना में 3 गुना या उससे भी ज़्यादा है। जिन देशों में प्रजनन दर 6 या ज़्यादा बच्चों की है, वहां गर्भनिरोध जानकारी और सेवाओं तक पहुंच सीमित है और 2 प्रतिशत से भी कम औरतें परिवार नियोजन का व्यवहार करती हैं।

अध्ययन किए गए कई देशों में शादी की उम्र, गर्भनिरोध उपयोग और कुल प्रजनन दर का औरत की शैक्षिक उपलब्धि, और आधुनिक क्षेत्र में सवैतनिक रोज़गार से सीधा संबंध था। उदाहरण के लिए कनाडा और फिनलैंड में, जहां अधिकांश औरतें परिवार नियोजन करती हैं, कम से कम 50 प्रतिशत वयस्क औरतें सवैतनिक औपचारिक श्रमिक वर्ग का हिस्सा है, इनमें से कम से कम 15 प्रतिशत व्यवसायिक व मैनेजरी पदों पर हैं। माली और अफगानिस्तान जिनमें प्रजनन स्तर उच्चतम और गर्भनिरोध उपयोग स्तर न्यूनतम है, में औरतों की शिक्षा और सवैतनिक रोज़गार की हालत निम्न स्तर की है। 15 वर्ष या इससे ज़्यादा उम्र की औरतों का मात्र एक प्रतिशत ही औपचारिक सवैतनिक कामों में नियुक्त है। इन देशों में कुल सवैतनिक कामगारों का क्रमशः 89 और 97 प्रतिशत आदमी हैं।

कई देशों में जल्दी बच्चा जनने और आगे चलकर अनियोजित गर्भ के कारण शिक्षा एवं आधुनिक क्षेत्र में रोज़गार के अवसरों में व्यवधान होता है। अधिकांश औद्योगिक देशों में औरतें गर्भनिरोध की आधुनिक विधियों और सुरक्षित गर्भपात की सुविधा उपलब्ध होने के कारण गर्भ का समय और बच्चों की संख्या पर आम तौर पर नियंत्रण कर पाती है। बहरहाल, अल्प विकसित देशों की 250 करोड़ औरतों के मामले में गर्भ अनियोजित होता है और सुरक्षित तरीके से समाप्त भी नहीं किया जा सकता।

एशिया के मुट्ठीभर देशों में गर्भनिरोध उपयोग

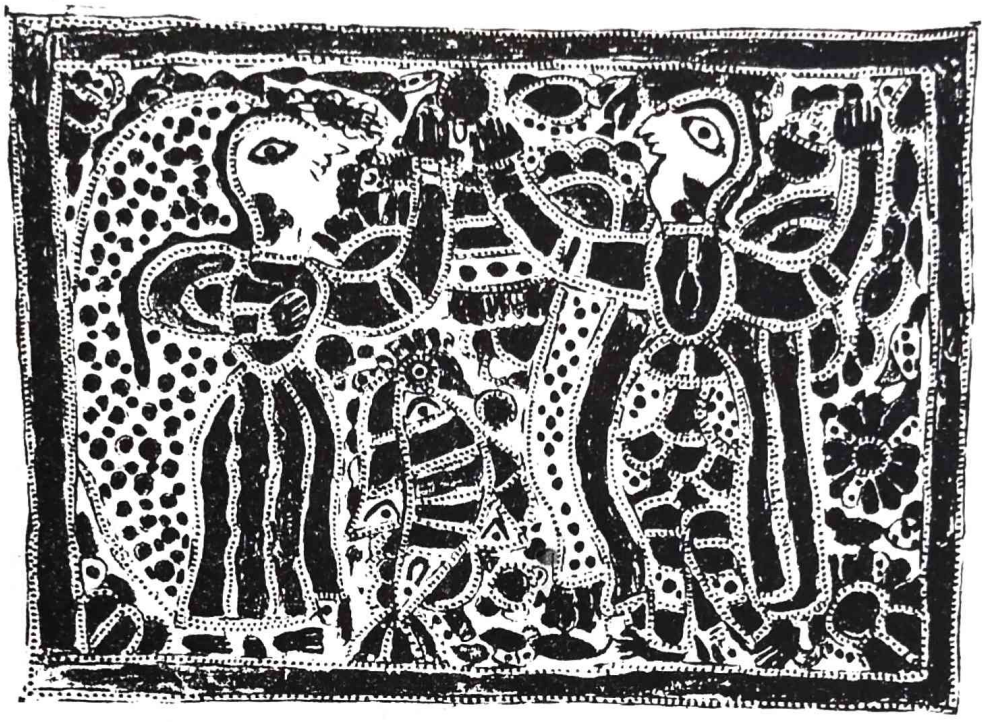

की ऊंची दरें हैं: ताईवान 78 प्रतिशत, चीन 70 प्रतिशत या ज़्यादा, हांगकांग, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया। कोई अचरज नहीं कि इन देशों में कुल प्रजनन स्तर भी कम है- एक से तीन बच्चे प्रति औरत और किशोर शादियों का स्तर भी कम है।

इसके दूसरे छोर पर कुछ अफ्रीकी और यथास्थितिवादी इस्लामिक देश, जैसे अफगानिस्तान, केमरून, इराक, लाइबेरिया, मलावी, माली, नाइजीरिया, उत्तरी यमन, पाकिस्तान, सेनेगल, सूडान और तंज़ानिया हैं, जहां औरतें जल्दी शादी करती हैं, और औसतन पांच से सात बच्चे पैदा करती हैं। इन देशों में 15 प्रतिशत से कम औरतें गर्भनिरोध का उपयोग करती हैं।

बगैर पति की औरतें

अध्ययन में शामिल सारे देशों में विधवा, तलाकशुदा और अलग रहने वाली महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा थी। देशों के बीच के अंतर काफी स्पष्ट थे। उदाहरण के लिए चीन में इन समूहों में 100 आदमियों की तुलना में 180 औरतें थीं। दुनिया भर में बंगलादेश में औरतों के दर्जे में सबसे निचली श्रेणी वाले उपरोक्त समूहों में प्रति 100 पुरुषों की तुलना में 927 औरतें थीं।

कई देशों के संदर्भ में महिला-मुखिया परिवारों के विषय में ये आंकड़े वास्तविक परिस्थिति को कम करके दिखाए हुए हो सकते हैं। ये ऐसे देश हैं जहां रोज़गार की तलाश में काफी पुरुष बाहर जाते हैं, जैसे दक्षिणी अफ्रीका। बहुत सारे देशों के बारे में उन परिवारों के समुचित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जिनमें औरतें अकेली कमाने वाली हैं। परंतु कुछ अनुमान बताते हैं कि पेरू, होंडुरास, वेनेजुएला और क्यूबा में 20 प्रतिशत शहरी और ग्रामीण परिवारों की मुखिया औरतें हैं। और ग्रामीण कीन्या, बोत्सवाना और घाना के कुछ हिस्सों में 40 प्रतिशत परिवारों में औरत एक मात्र कमाऊ सदस्य है। तुलना के लिए अमरीका में कुल परिवारों का छठवां हिस्सा ही ऐसा है जिनकी मुखिया अविवाहित औरतें हैं- यह ऊंची तलाक दर और अविवाहित किशोरियों के बच्चों की संख्या में वृद्धि के कारण है। अमरीकी कल्याण कार्यक्रम के भुगतान का एक बड़ा हिस्सा अविवाहित महिला-मुखिया परिवार को जाता है- इससे संकेत मिलता है कि गरीबी का नारीकरण मात्र गरीब देशों में ही नहीं होता।

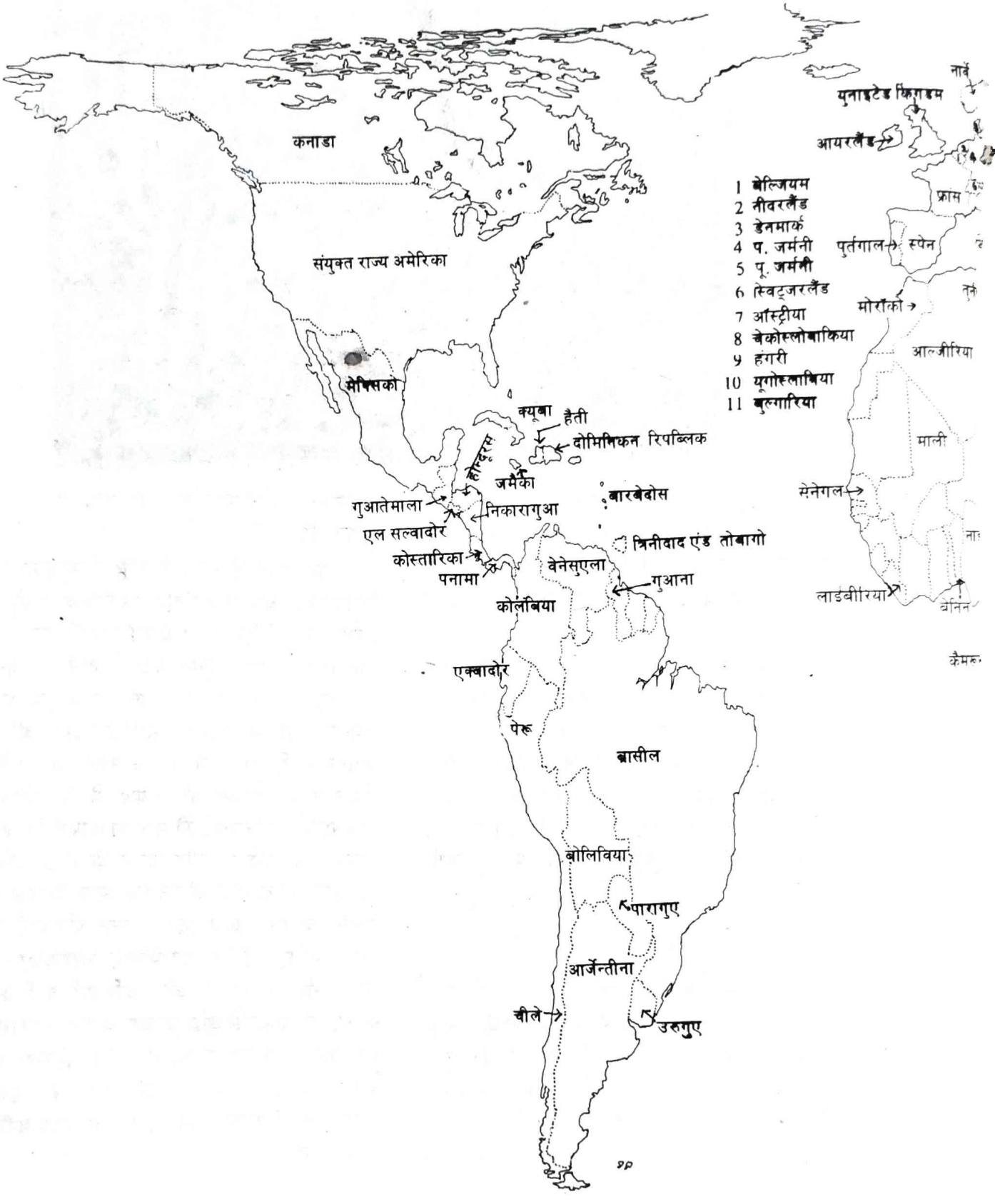

नार्वे
युनाइटेड किंगडम
आयरलैंड
कनाडा
1 बेल्जियम
2 नीदरलैंड
3 डेनमार्क
4 प. जर्मनी
5 पू. जर्मनी
6 स्विट्जरलैंड
7 आस्ट्रीया
8 चेकोस्लोवाकिया
9 हंगरी
10 युगोस्लाविया
11 बुल्गारिया
फ्रांस
पुर्तगाल
स्पेन
संयुक्त राज्य अमेरिका
मोरॉको
आल्जीरिया
मैक्सिको
क्यूबा
हैती
दोमिनिकन रिपब्लिक
माली
जमैका
बारबेदोस
सेनेगल
गुआतेमाला
निकारागुआ
एल सल्वादोर
त्रिनीदाद एंड तोबागो
कोस्तारिका
पनामा
वेनेसुएला
गुआना
लाइबीरिया
कोलंबिया
एक्वादोर
पेरू
ब्रासील
बोलिविया
पारागुए
आर्जेन्तीना
चीले
उरुगुए

फिनलैंड
सोवियत संघ
पोलैंड
रुमानिया
तुर्की
ग्रीस
इज़राइल
ईराक
कुवैत
जॉर्डन
लिबिया
मिस्र
संयुक्त अरब अमीरात
साउदी अरब
उ. यमन
सूदान
अफगानिस्तान
पाकिस्तान
नेपाल
चीन
भारत
बंगलादेश
ब. कोरिया
जापान
ताइवान
हाँग काँग
थाइलैंड
फिलिपीन्स
श्रीलंका
मलेशिया
सिंगापुर
इंदोनेशिया
कीन्या
रुआण्डा
तन्जानिया
मोजाम्बीक
जाम्बिया
मलावी
जिम्बाब्वे
बोत्स्वाना
अफ्रीका
लेसोतो
ऑस्ट्रेलिया
न्यूजीलैंड

शिक्षा

औरतों की ज़िन्दगी में परिवर्तन के लिए एक बड़ी शक्ति शिक्षा है। यह उन क्षेत्रों में से भी एक है जिनमें औरतों ने हाल में बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं। निर्धनतम देशों में भी सरकारों ने पिछले कुछ दशकों में काफी धन शिक्षा में निवेश किया है।

चूंकि शिक्षा का प्रभाव औरतों के सवैतनिक रोज़गार के अवसरों, उनकी कमाने की क्षमता, शादी की उम्र, बच्चे जनने पर नियंत्रण, कानूनी व राजनैतिक अधिकारों के उपयोग, और यहां तक कि खुद की और अपने बच्चों की देखभाल पर भी पड़ता है इसलिए अक्सर शिक्षा औरतों के लिए बढ़ते अवसरों की अग्रगामी होती है। हालांकि लिंग अंतर कम होने शुरू हुए हैं परंतु दुर्भाग्यवश अभी भी आदमियों की साक्षरता दर औरतों से ज़्यादा है और स्कूल में अभी भी संख्या में लड़के, लड़कियों से ज्यादा होते हैं।

इस अध्ययन में औरतों की शैक्षिक स्थिति का मापन चार कारकों के तहत किया गया है। आंकड़ों का प्रमुख आधार यूनेस्को, यू.एस. ब्यूरो ऑफ सेंसस, जनसंख्या परिषद् और विश्व बैंक हैं।

* **प्राथमिक और माध्यमिक शाला दर्ज संख्या-** इसका अर्थ है प्राथमिक और माध्यमिक शाला योग्य उम्र की कुल लड़कियों में से वास्तव में स्कूल में दाखिल लड़कियों का प्रतिशत।

* **माध्यमिक शालाओं में महिला शिक्षिकाएं-** माध्यमिक शाला शिक्षकों में से महिला शिक्षिकाओं का प्रतिशत जिन देशों का कुल महिला स्थिति सूचकांक अच्छा है वहां करीब आधी माध्यमिक शिक्षक महिलाएं हैं।

* **विश्वविद्यालय में दर्ज संख्या-** 20 से 24 वर्ष उम्र की औरतों में से विश्वविद्यालय में दर्ज औरतों का प्रतिशत।

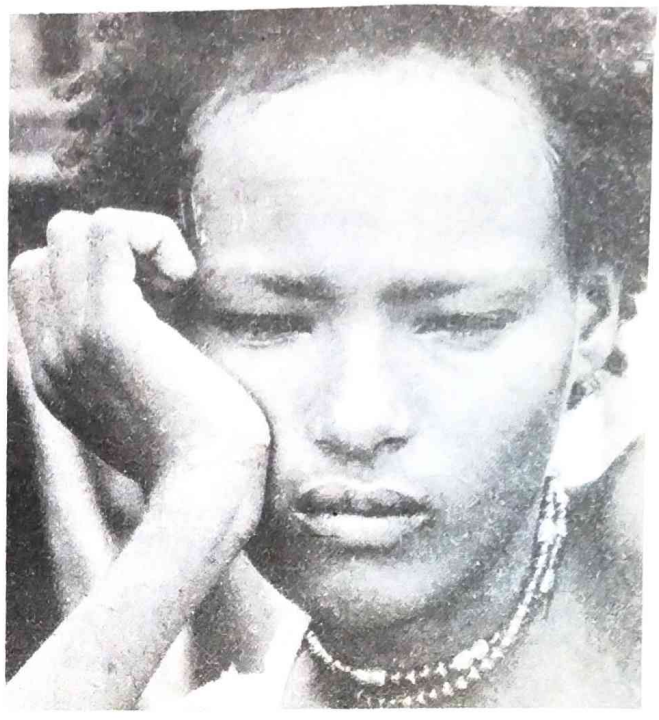

* **लिंग भेद-** आदमी व औरत की भिन्न-भिन्न साक्षरता दर अर्थात् 15 से 44 वर्ष के स्त्री व पुरुषों की साक्षरता दर का अंतर। यह अंतर उच्च व मध्यम आय राष्ट्रों में काफी कम हो गया है।

स्कूलों में लड़कियां

उत्तरी अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और पश्चिमी यूरोप के अधिकांश हिस्सों में स्कूली उम्र की लगभग सारी लड़कियां प्राथमिक या माध्यमिक शालाओं में दाखिल हैं। हालांकि माध्यमिक स्तर पर शाला त्याग अमरीका जैसे कुछ देशों में आज भी एक समस्या है। शेष दुनिया में आंकड़े, बार्बेडोज़ में शत-प्रतिशत दर्ज संख्या से लेकर अफगानिस्तान में 9 प्रतिशत तक है। लातिनी अमरीका में लड़कियों की दर्ज संख्या 80 प्रतिशत तक है। अधिकांश मुस्लिम देशों में लड़कियों की दर्ज संख्या काफी कम है- तेल-समृद्ध सऊदी अरब में 46 प्रतिशत और पाकिस्तान में मात्र 17 प्रतिशत।

ऊंची जन्मदर और लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था के चलते अधिकांश गरीब देश स्कूली उम्र बच्चों की बढ़ती जनसंख्या से तालमेल नहीं रख पाते। जहां स्कूलों में जगह की कमी है वहां लड़कियां नुकसान उठाती हैं, खासकर ऊंची कक्षाओं में। राष्ट्र संघ के अनुसार करीब एक तिहाई विकासशील देशों में सारे बच्चों की शिक्षा के लिए समुचित स्कूली व्यवस्था नहीं है।

कुछ देशों में लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ पूर्वाग्रहों और वयस्क औरतों की निम्न कमाई क्षमता का एक दुष्चक्र बन जाता है। मां-बाप लड़के को शिक्षित करना आंशिक रूप से इसलिए बेहतर समझते हैं क्योंकि उसकी नौकरी के आसार बेहतर होते हैं। मां-बाप लड़कियों का स्कूल इसलिए भी छुड़वा देते हैं क्योंकि लड़कियों को घर पर मदद करना चाहिए। जब लड़कियों को स्कूल में टिकने भी दिया जाता है तब भी उन्हें अपने भाइयों की तुलना में पढ़ाई के लिए कम समय मिलता है। कुछ देशों में मां-बाप लड़कियों को रजस्वला होने पर स्कूल से हटा लेते हैं क्योंकि या तो वे शादी योग्य मानी जाती हैं या मां-बाप उनके कौमार्य की रक्षा करना चाहते हैं। अधिकांश देश आज भी लड़कियों को स्कूल में दाखिल करवाने या बनाए रखने का समुचित प्रयास नहीं करते।

महिला शिक्षिकाएं

जिन समुदायों में कई वयस्क अल्पशिक्षित या अशिक्षित हों, उनमें शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। ऐसे समुदायों में स्कूली लड़कियों की प्रमुख आदर्श महिला उनकी शिक्षिका होती हैं। यूनेस्को के अनुसार महिला शिक्षिका की उपस्थिति का भी लड़कियों की दर्ज संख्या पर अच्छा असर पड़ सकता है।

महिला शिक्षिकाओं का प्रभाव अक्सर सीमित होता है क्योंकि वे सबसे निचली श्रेणी में होती हैं। कई देशों में कम वेतन के कारण प्राथमिक स्कूल औरतों के लिए आर्थिक आश्रय स्थल बन गए हैं। परिस्थिति का थोड़ा ज़्यादा बेहतर सूचक माध्यमिक स्कूलों में महिलाओं की संख्या हो सकता है।

अधिकांश औद्योगिक देशों और कुछ विकासशील

शिक्षा

स्कोर	देश
18.5	संयुक्त राज्य
18.0	जमैका
17.5	आर्जेन्तीना
16.5	कनाडा
16.0	फिनलैंड, फ्रांस, नार्वे, वेनेसुएला
15.5	बेल्जियम, बुल्गारिया, डेनमार्क, पू. जर्मनी, इज़्राइल, स्वीडन, ताइवान
15.0	ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, इटली
14.5	बारबेदोस, हंगरी, न्यूज़ीलैंड, पोलैंड, स्पेन
14.0	ऑस्ट्रीया, कोस्तारिका, प. जर्मनी, जॉर्डन, लेसोतो, पनामा, फिलिपीन्स, यूनाइटेड, किंगडम, उरुगए, यूगोस्लाविया
13.5	चीले, क्यूबा, चेकोस्लोवाकिया, एक्वादोर, ग्रीस, नीदरलैंड, पारागुए, स्विट्जरलैंड
13.0	जापान, कुवैत, निकारागुआ, पुर्तगाल, रुमानिया
12.5	ब्रासील, कोलंबिया, सिंगापुर, त्रिनीदाद एंड तोबागो, संयुक्त अरब अमीरात
12.0	हाँग काँग, पेरु, द. अफ्रीका, सोवियत संघ
11.5	बोत्स्वाना, गुआना, द. कोरिया, मेक्सिको
11.0	होन्दूरस, थाइलैंड
10.0	बोलिविया, ईराक, मलेशिया, श्रीलंका
9.5	आल्जीरिया, दोमिनिक्न, रिपब्लिक, इंदोनेशिया, ज़िम्बाब्वे
9.0	एल सल्वादोर
8.5	मिस्र
8.0	कीन्या, साउदी अरब, ज़ाम्बिया
7.5	गुआतेमाला
7.0	चीन, मोज़ाम्बीक, सिरिया, तुर्की
6.5	नाईजीरिया, तुनीसिया
6.0	कैमरून, हैती, भारत, मोरॉको, तन्ज़ानिया
5.5	अफगानिस्तान, मलावी, रुआण्डा, सूदान
5.0	पाकिस्तान

देशों में माध्यमिक स्कूलों के आधे या उससे भी ज़्यादा शिक्षक महिलाएं हैं। उदाहरण के लिए अर्जेन्टीना और जमैका में यह संख्या दो तिहाई है (यह एक रोचक तथ्य है कि जमैका उन थोड़े से देशों में से एक है जहां औरतों का साक्षरता प्रतिशत आदमियों से ज़्यादा है)।

महिला माध्यमिक शिक्षिकाओं का प्रतिशत सबसे कम उत्तरी यमन (8 प्रतिशत), बंगलादेश व नेपाल (9 प्रतिशत), हइटी (12 प्रतिशत) और सेनेगल (15 प्रतिशत) में है।

विश्वविद्यालयों में दर्ज संख्या

औद्योगिक देशों में माध्यमिक शाला का प्रमाण-पत्र अच्छी नौकरियों की शर्त बनता जा रहा है। औरतें, जिनका बेहतर वेतन वाले औद्योगिक नौकरियों में अनुपात कम है, के लिए विश्वविद्यालय की डिग्री अच्छे कैरियर की कुंजी है।

विश्वविद्यालयीन शिक्षा एकरूप नहीं है। इसलिए आपस में इनकी तुलना नहीं की जा सकती। परंतु इन अंतरों के बावजूद भी महिलाओं की 59 और 46 प्रतिशत विश्वविद्यालयीन दर्ज संख्या के कारण अमरीका और कनाडा विश्व में अलग स्थान रखते हैं। यूरोप के देशों में दर्ज संख्याएं रूमानिया के लिए 10 प्रतिशत से लेकर स्वीडन के लिए 39 प्रतिशत तक है। दक्षिणी व मध्य अमरीका के मामले में अर्जेन्टीना में 39 प्रतिशत, तो ग्वाटेमाला और गुयाना में 2 प्रतिशत है। सबसे निचले 16 देशों में महिला दर्ज संख्या 1 प्रतिशत से भी कम है। इन देशों में पुरुषों की दर्ज संख्या भी बहुत कम है।

साक्षरता में लिंग अंतर

वयस्क साक्षरता दर वास्तव में प्राथमिक शिक्षा दाखिलों में ऐतिहासिक रुख को ही प्रतिबिंबित करती है, हालांकि चीन जैसे कुछ देशों में प्रौढ़ साक्षरता के कार्यक्रम भी चलते हैं। 1960 व 70 के दशक में जो विशाल दाखिला अभियान चले, उनके कारण विश्व स्तर पर निरक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत घटकर 30 रह गया है। परंतु आज भी अधिकांश देशों में निरक्षर महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। अध्ययन में शामिल 99 देशों में से करीब 20 प्रतिशत से ज्यादा में साक्षर पुरुषों की संख्या साक्षर औरतों के मुकाबले 25 से 50 प्रतिशत ज्यादा थी। सबसे ज्यादा अंतर लिबिया में देखा गया। जिन देशों में लिंग भेद ज्यादा है, वे हैं बेनिन, सिरिया, तंजानिया और टर्की। औद्योगिक देशों को छोड़कर जहां लगभग सभी साक्षर हैं, मात्र 6 ऐसे विकासशील देश हैं जिनमें स्त्री-पुरुष साक्षरता दरों में कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं है। कुछ विकासशील देशों, जैसे, बोत्सवाना, लीसोथो और जमैका में महिला साक्षरता पुरुषों से ज्यादा है।

रोज़गार

औरतें दुनिया के कामगारों का एक तिहाई हिस्सा है और यह अनुपात पिछले दशक में ज्यादा नहीं बदला है हालांकि इस दौरान महिला कामगारों की संख्या में 10 करोड़ की वृद्धि हुई है। सन् 1985 और 2000 के बीच दुनिया के कामगारों की संख्या में 60 करोड़ की वृद्धि होगी। अधिकांश विकासशील देशों में श्रमिकों की वृद्धि की तुलना में आर्थिक विस्तार पिछड़ गया है जिससे औरत-आदमियों दोनों के लिए अवसर कम हुए हैं। ज्यादा गतिशीलता, ऋण तक आसान पहुंच और शिक्षा में ज्यादा उपलब्धियों के कारण रोज़गार के क्षेत्र में पुरुषों ने औरतों पर काफी बढ़त बरकरार रखी है।

दुर्भाग्यवश श्रमशक्ति संबंधी अधिकांश अधिकारिक आंकड़ों में औरतों की आर्थिक भागीदारी को कम करके आंका गया है, खासकर गरीब ग्रामीण देशों में जहां की अधिकतर जनसंख्या जूझकर मात्र जीने लायक खेती में लगी है। उदाहरण के लिए अफ्रीका में किए गए घर-घर सर्वे से पता चलता है कि औरतें खेती बाड़ी का तीन चौथाई काम करती हैं; एशिया के अधिकांश हिस्सों में वे आधा काम करती हैं। कुछ औरतें "सूक्ष्म-उद्यमों" में लगी हैं- बहुत ही छोटे पैमाने का व्यापार या उत्पादन कार्य, अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र में। अवैतनिक कृषि कार्यों के समान ही ये गतिविधियां भी सरकारी आंकड़ों में कम प्रतिबिम्बित होती हैं।

दरअसल औरतों की आर्थिक उत्पादकता और आय क्षमता के अच्छे आंकड़े बहुत ही कम हैं, जिनसे कि देशों के बीच तुलना की जा सके। इस अध्ययन में औपचारिक अर्थव्यवस्था में औरतों की भागीदारी को आसानी से उपलब्ध चार सांख्यिकी सेटों के आधार पर मापा गया। मुख्य सांख्यिकी स्रोत थे: अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय, यू.एस. ब्यूरो ऑफ सेंसस, राष्ट्र संघ सांख्यिकी कार्यालय और जनसंख्या परिषद्।

* **रोजगार प्राप्त औरतें-** 15 वर्ष से ऊपर की औरतों में से उन औरतों का प्रतिशत जो वेतन पर काम करती हैं। औद्योगिक देशों में जहां सारे परिवार "धन की अर्थव्यवस्था" के अंग हैं वहां यह औरतों की आर्थिक भागीदारी का अच्छा मापदंड है पर उनकी कमाने की वास्तविक क्षमता का नहीं।

* **स्वरोज़गारी औरतें-** 15 वर्ष से ऊपर की औरतों में से उन औरतों का प्रतिशत जो अधिकारिक रूप से स्व रोज़गार प्राप्त श्रेणी में आती हैं, चाहे वे कृषि, व्यापार, उत्पादन या कोई व्यवसाय करती हों और चाहे वे किसी और को नियुक्त करती हों अथवा नहीं। कुछ विकासशील देशों में यह सूचक मात्र यह बताता है कि वहां की सरकार ने कितनी कर्मठता से औरतों के काम को नापने की कोशिश की है।

* **व्यवसायिक औरतें-** 15 वर्ष से ऊपर की औरतों में से उन औरतों का प्रतिशत जो किसी व्यवसायिक, तकनीकी, प्रबंधकीय या प्रशासनिक रोज़गार में हैं।

* **लिंग भेद: सवैतनिक रोज़गार में औरतों का हिस्सा-** अधिकारिक सवैतनिक कामगारों में औरतों का प्रतिशत।

रोज़गार

स्कोर	देश
14.5	स्वीडन
13.5	पू. जर्मनी
12.5	मोज़ाम्बीक, सोवियत संघ
11.5	बारबेदोस, फिनलैंड
10.0	डेनमार्क, नार्वे
10.5	बुल्गारिया
10.0	कनाडा, चेकोस्लोवाकिया, संयुक्त राज्य
9.5	हैती, जमैका
9.0	ऑस्ट्रेलिया, हंगरी
8.5	बेनिन, हाँगकाँग, पोलैंड, त्रिनीदाद एंड तोबागो, यूनाइटेड किंगडम
8.0	प. जर्मनी, इज़राइल, पेरु, पुर्तगाल, सिंगापुर
7.5	ऑस्ट्रीया, फ्रांस, इटली, जापान, नेपाल, पनामा, फिलिपीन्स, स्विट्ज़रलैंड, तन्ज़ानिया, उरुगुए
7.0	बेल्जियम, आयरलैंड, द. कोरिया, नीदरलैंड, न्यूज़ीलैंड, थाइलैंड
6.5	बोत्स्वाना, चीन, दोमिनिकन रिपब्लिक, रुमानिया, ताइवान, वेनेसुएला, यूगोस्लाविया
6.0	आर्जेन्तीना, ब्रासील, कोस्तारिका, क्यूबा, एल सल्वदोर, इंदोनेशिया, कुवैत, मलेशिया, निकारागुआ, द. अफ्रीका, श्रीलंका
5.5	चीले, ग्रीस, कीन्या, स्पेन
5.0	बोलिविया, कैमारून, एक्वादोर, मेक्सिको, नाईजीरिया, रुआण्डा, ज़ाम्बिया
4.5	कोलंबिया, गुआना, भारत, पारागुए
4.0	गुआतेमाला, होन्दूरस
3.5	सेनेगल, तुनीसिया, ज़िम्बाब्वे
3.0	बंगलादेश, मिस्र, लेसोतो, लाईबीरिया, मोरॉको, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात
2.5	जॉर्डन, मलावी, माली, सूदान, सिरिया
2.0	अफगानिस्तान, आल्जीरिया, ईराक, लिबिया, पाकिस्तान, साउदी अरब, उ. यमन

सवैतनिक महिला कर्मचारी

वेतन पर काम करने वाली औरतों का अनुपात देश-देश में बदलता है। संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, उत्तरी यूरोप और अधिकांश पूर्वी यूरोप में अधिकारिक सवैतनिक कामगारों में महिलाओं का प्रतिशत 40 है, जबकि अधिकांश अरब देशों में यह 8 प्रतिशत से भी कम है। विश्वव्यापी विभिन्नताओं में आंशिक रूप से देशों के आर्थिक विकास की स्थिति (या ज्यादा विशिष्ट रूप से संगठित क्षेत्र का आकार) प्रतिबिम्बित होता है, किन्तु इससे औरतों के सवैतनिक रोज़गार के रास्ते में सांस्कृतिक व अन्य अवरोधों का भी आभास मिलता है।

अध्ययन किए गए देशों में अधिकारिक सवैतनिक कामगारों में औरतों का सबसे कम प्रतिशत सामान्य तौर पर अफ्रीका, मध्यपूर्व, और दक्षिण एशिया में पाया गया। अफगानिस्तान, केमरून, लाइबेरिया, मलावी, माली, नेपाल, उत्तरी यमन, पाकिस्तान, खाण्डा, सऊदी अरब, और सूडान में यह 2 प्रतिशत से कम था। खाण्डा जैसे न्यूनतम विकसित देशों में (वार्षिक प्रति व्यक्ति आय 290 डालर) संगठित क्षेत्र इतना छोटा है कि महिलाओं की आर्थिक भागीदारी मापने के लिए यह सूचकांक अप्रासंगिक है। दूसरी ओर सऊदी अरब में औरतों की निम्न रोज़गार दर, औरतों के रोज़गार संबंधी सांस्कृतिक अवरोधों का द्योतक है। इसके विपरीत स्वीडन, पूर्वी जर्मनी और सोवियत संघ में 60 प्रतिशत सवैतनिक श्रमिकों में शुमार हैं।

हालांकि औरतों द्वारा घर से बाहर पूर्णकालिक सवैतनिक काम करने के बारे में सांस्कृतिक अवरोध हर जगह कम हो रहे हैं, परंतु लगभग सभी जगह औरतों पर बच्चों और घरेलू काम की पूरी जिम्मेदारी है, जिसमें ग्रामीण घरों में पशुओं की देखभाल और खाद्य उत्पादन भी शामिल है। अधिकांश देशों में बदलते आर्थिक हालातों के कारण औरतें तेज़ी से सवैतनिक कामगार समूह में शामिल हो रही हैं, ताकि पारिवारिक खर्च पूरा करने में मदद दे सकें या बढ़ती हुई संख्या में वे अपने बच्चों का एकमात्र सहारा हैं।

सारी दुनिया में कामगार औरतों के लिए परिवार और काम की मांगों के बीच संतुलन बैठाने की जरूरत का असर उनकी आर्थिक क्षमता और दैनिक जीवन पर पड़ता है। विकसित और विकासशील दोनों देशों में औरतें अपने पतियों की तुलना में कम फालतू समय पाती हैं- जो कि न सिर्फ आराम और मनोरंजन के लिए बल्कि अपने कौशल को आगे बढ़ाने और सामुदायिक मामलों में भागीदारी के लिए भी चाहिए।

ग्रामीण बंगलादेशी आदमी और औरत अपना दिन किस तरह बिताते हैं, इस बारे में किए गए एक अध्ययन

से पता चला है कि एक औसत औरत दिन में 9 से 10 घंटे काम करती है जबकि उसका पति 7 से 8 घंटे। औरत करीब 6 घंटे खेतीबाड़ी के काम और परिवार के लिए पानी व ईंधन प्राप्त करने में लगाती है। उसका पति 3 से 4 घंटे लगाता है। औरत बच्चों की देखभाल, खाना पकाने और अन्य घरेलू कामों में 2-3 घंटे लगाती है जबकि पति 5 मिनट भी नहीं लगाता।

औरतों के पास बहुत कम फालतू समय होता है। इस तथ्य का असर स्त्री साक्षरता दर बढ़ाने, स्त्री कृषकों को खेतीबाड़ी की ट्रेनिंग देने, या औरतों को स्थानीय विकास परियोजनाओं में भागीदार बनाने के प्रयासों पर होता है। जब औरतों को ऐसे अवसर दिए भी जाते हैं, तो उनमें से कई के पास भाग लेने के लिए समय नही होता।

स्वाश्रयी औरतें

विश्व में औरतों की बड़ी संख्या किसी न किसी तरह से स्वरोजगार प्राप्त हैं। इनमें से अधिकांश परिवार भी छोटी-मोटी खेती में सहकर्मी के रूप में कार्यरत हैं। परंतु चूंकि अधिकांश सरकारी आंकड़ों में मात्र पति को किसान के रूप में दर्ज किया जाता है इसलिए स्वाश्रयी श्रेणी में खेतिहर औरतों की संख्या बहुत कम गिनने में

लिंग भेद
अधिकतम स्कोर-25

सबसे खराब 12 स्कोर		सबसे श्रेष्ठ 12 स्कोर	
बंगलादेश	5.5	फिनलैंड	23.5
साउदी अरब	6.5	स्वीडन	23.0
मिस्र	7.5	सोवियत संघ	23.0
सिरिया	8.5	नार्वे	22.0
नाईजीरिया	8.5	संयुक्त राज्य	22.0
लिबिया	9.0	ऑस्ट्रेलिया	21.5
पाकिस्तान	9.5	बुल्गारिया	21.5
मोरॉको	9.5	कनाडा	21.5
उ. यमन	10.0	चेकोस्लोवाकिया	21.5
सूदान	10.0	डेनमार्क	21.5
माली	10.0	पू. जर्मनी	21.5
कुवैत	10.0	हंगरी	21.5

आती है। तंजानिया और नेपाल दो अपवाद हैं जहां कुल औरतों में से आधी स्वाश्रयी के रूप में गिनी जाती हैं। इनमें से अधिकांश खेती में लगी हैं। यह बात वास्तव में सारे अफ्रीकी और अधिकतर एशियाई देशों के लिए भी उतनी ही सही है परंतु आंकड़ों में दिखती नहीं।

पश्चिमी अफ्रीका और लातिनी अमरीका के कुछ भागों में औरतें बड़ी संख्या में व्यापार-व्यवसाय में लगी हैं। इन गतिविधियों के आधार पर बेनिन, केमरून, हेइटी, नाइजीरिया, पेरू और खाण्डा की स्वाधारित औरतों के आंकड़े समझने में मदद मिलती है। इन देशों में एक-चौथाई से एक तिहाई तक औरतें स्वाधारित की गिनती में आती हैं।

सरकारी आंकड़ों में औरतों की गिनती उद्यमी के रूप में होगी या नहीं, यह उनके व्यवसाय के आकार पर निर्भर करता है। अधिकांश धंधे छोटे-छोटे होते हैं, मुख्यतः औरतें ऋण प्राप्ति में अवरोधों के कारण समुचित पूंजी जुटा पाने में असमर्थ रहती हैं (एक अवरोध किसी भी प्रकार की संपत्ति पर उनका अधिकार न होना भी है)। समय की सीमा और शिक्षा का स्तर कम होने के कारण छोटे व्यवसाय वाली औरतें आदमियों की तुलना में लालफीताशाही से कम जूझ पाती हैं, जिससे वे अधिकारिक लायसेंस से वंचित रह जाती हैं।

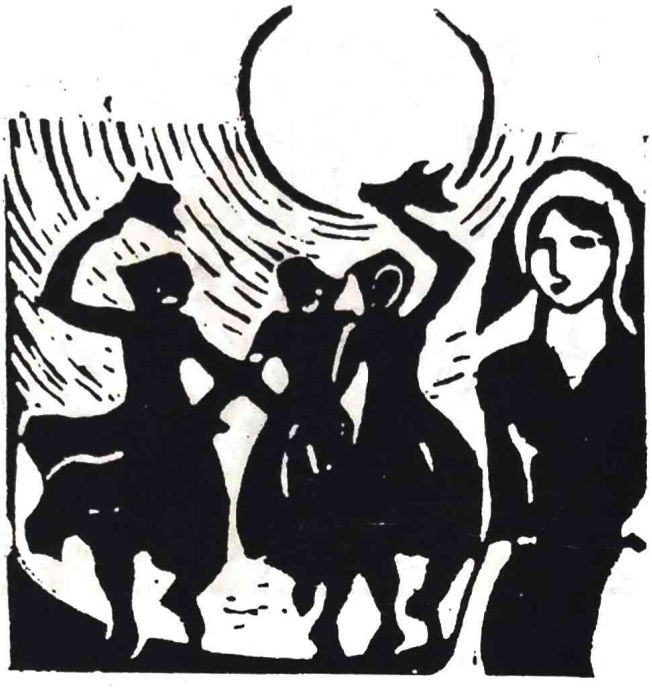

व्यवसायिक औरतें

व्यवसायिक पदों पर औरतों का प्रतिशत उन कुछेक उपलब्ध मानदंडों में से है जिनसे औरतों की तुलनात्मक आर्थिक स्थिति का पता चलता है, क्योंकि इससे उनकी आय उपार्जन क्षमता और प्रतिष्ठा का संकेत मिलता है। इस मानदंड से पता चलता है कि औरतों की तुलनात्मक शैक्षिक उपलब्धि क्या है और उन्हें किस तरह की पढ़ाई के अवसर दिए जाते हैं या प्रोत्साहित किया जाता है।

औरतों की कम शैक्षणिक उपलब्धि के कारण सभी देशों में उनकी वास्तविक आय पुरुषों से कम रहती है। अध्ययन में सर्वोत्तम स्कोर वाले देश स्वीडन में पुरुष 10 क्रोनर कमाता है और औरत 9 क्रोनर कमा पाती है। सोवियत संघ में औरतों की आय पुरुषों की आय का 75 प्रतिशत और संयुक्त राज्य अमरीका में 68 प्रतिशत है।

पुरुषों के मुकाबले औरतों की कम कमाई का प्रमुख कारण यह है कि वे भिन्न किस्म के काम करती हैं। औरतों के लिए उपलब्ध नौकरियों का दायरा पुरुषों के मुकाबले ज्यादा संकीर्ण है। हर अर्थव्यवस्था में "स्त्रियोचित क्षेत्र" बन गए हैं जिनमें वेतनमान, अन्य भत्ते और कार्य परिस्थितियां और उन्नति की संभावनाएं कम हैं। इनमें शामिल हैं: मिस्र में कपास तोड़ना, श्रीलंका में चाय तोड़ना, पुर्तगाल में घरेलू काम, मेक्सिको में इलेक्ट्रानिक्स, और ब्रिटेन में सेक्रेटरी की नौकरियां।

अध्ययन में शामिल 99 देशों में से 13 को छोड़कर बाकी सबमें 10 प्रतिशत से कम औरतें अपेक्षाकृत बेहतर आय वाली व्यवसायिक, तकनीकी, प्रबंधकीय या प्रशासनिक नौकरियों में लगी हैं। करीब आधे देशों में तो यह प्रतिशत 3 या उससे भी कम है। अन्य कई सूचकांकों की तरह इस मामले में स्वीडन सबसे ऊपर है: 42 प्रतिशत औरतें व्यवसायिक नौकरियों में हैं।

लिंग भेद: कुल श्रमशक्ति में औरतों का हिस्सा

अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय के आंकड़े बताते हैं कि विश्व श्रम शक्ति में औरतों का सबसे कम हिस्सा लातिनी अमरीका में और सबसे बड़ा हिस्सा पूर्वी यूरोप में है। अधिकांश लातिनी अमरीकी देशों में अधिकारिक श्रमशक्ति का एक तिहाई से कम हिस्सा औरतों का है जबकि कुछ पूर्वी यूरोपीय देशों में यह लगभग आधा है। उत्तरी अमरीकी औरतों का 45 प्रतिशत भी काफी अच्छा है। एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी यूरोप में मोटे-मोटे तौर पर हर तीन कामगारों में से एक औरत है। औरतों की हालत स्केण्डिनेविया और नव औद्योगिक एशियाई देशों में भी अच्छी है जहां वे सवैतनिक श्रमिकों में 50 प्रतिशत से थोड़ी ही कम हैं। औरतें सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और हांगकांग में सवैतनिक श्रमिकों की 40 प्रतिशत हैं। मोज़ाम्बिक जैसे कुछ विकासशील देशों में रोज़गार में औरतों का हिस्सा थोड़ा अजीबोगरीब लगता है क्योंकि वहां से भारी संख्या में पुरुष कामगार दूसरे देशों में पलायन करते हैं।

सामाजिक समता

पिछले कुछ दशकों में अधिकांश देशों ने औरतों और मर्दों के बीच बराबरी को बढ़ाने के लिए संवैधानिक या कानूनी प्रावधान बनाए हैं। इनमें पारिवारिक कानून सुधार, बराबर वेतन, उचित रोजगार सुरक्षा और बढ़े हुए राजनैतिक अधिकार शामिल हैं। इन नए अधिकारों का औरतों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति पर कितना वास्तविक असर पड़ा है इसे नापने का सबसे अच्छा तरीका शायद लिंग भेद के आंकड़े हैं, जैसे सवैतनिक कामगारों में औरतों की भागीदारी। इन मापदंडों में कई ऐसे देशों के अंक बहुत कम आए हैं, जहां अच्छे कानून मौजूद हैं क्योंकि सरकार इन कानूनी सुधारों को लागू करवा पाने में या तो अक्षम है या इच्छा का अभाव है।

इस प्रकार की असंगतियों के कारण ही कानून की नजर में औरतों की वास्तविक बराबरी को आंक पाना किसी और पहलू से ज्यादा कठिन है। इस अध्ययन में देशों के बीच औरतों की सामाजिक बराबरी की तुलना के लिए तीन कारकों का इस्तेमाल किया गया है। इन तीनों स्कोरों का औसत लिंग भेद के सूचक का काम करता है। आंकड़ों का मुख्य स्रोत है- द इकॉनॉमिस्ट द्वारा प्रकाशित चार्ल्स हुमाना की द वर्ल्ड ह्यूमॅन राइट्स गाइड (विश्व मानव अधिकार गाइड)।

* **राजनैतिक व कानूनी बराबरी-** इससे नापा जाता है कि किस हद तक औरतें हर तरह के लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ कानूनी सुरक्षा की अपेक्षा कर सकती हैं, और किस हद तक वे अपने राजनैतिक अधिकारों का उपयोग कर सकती हैं। इसमें राजनैतिक पद पर प्रतिनिधित्व भी शामिल है।

* **आर्थिक बराबरी-** इससे नापा जाता है कि किस हद तक औरतें कार्यस्थल पर अपने पुरुष सहकर्मियों के साथ बराबरी के व्यवहार की अपेक्षा कर सकती हैं और क्या वे अन्य मामलों में भी जीवन के आर्थिक पहलुओं में बराबरी से भाग ले सकती हैं। इसमें वास्तविक संपत्ति पर मिल्कियत, प्रबंध का हक और विरासत शामिल है।

* **विवाह और परिवार में बराबरी-** इसमें स्वतंत्र रूप से विवाह करने का हक, तलाक और पारिवारिक कानून में बराबरी का हक शामिल है।

राजनैतिक और कानूनी बराबरी

इकॉनॉमिस्ट के आंकड़े बताते हैं कि केवल दो देशों, फिनलैंड और स्वीडन, ने ही औरतों के लिए समान राजनैतिक हक और लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ कानूनी सुरक्षा का साफ संकल्प जाहिर किया है। इस संकल्प के बावजूद भी सरकार में औरतों का प्रतिनिधित्व कम है। वर्तमान में स्वीडन संसद की एक तिहाई सीटों पर औरतें हैं। अन्य देशों में सरकार की सर्वोच्च परिषदों (संसद वगैरह) में औरतों का प्रतिशत यदाकदा ही 10 से ऊपर होता है।

राजनैतिक और कानूनी बराबरी में सबसे कम अंक वाले दो देश हैं सऊदी अरब और पाकिस्तान, जहां अन्य मापदण्डों में भी स्कोर बहुत कम हैं। इन देशों में धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं पर आधारित कानून वास्तव में औरतों की परवश स्थिति को पुख्ता करते हैं।

आर्थिक बराबरी

कार्यस्थल पर गैरबराबरी किसी हद तक हर देश में है। बराबरी की कानूनी गारंटी को आर्थिक हकीकत में तबदील करने के लिए सरकार, नियोक्ताओं, नेताओं

और आर्थिक शक्ति संपन्न सभी लोगों द्वारा सचेष्ट प्रयासों की जरूरत होती है। इसके अंतर्गत आर्थिक जीवन में पूर्ण भागीदारी के अवरोध को हटाने व उत्पादकता को पुरस्कृत करने की कार्यवाहियां शामिल हैं। अध्ययन में शामिल आधे देशों ने वेतनमान व भत्ते की बराबरी और औरतों को ऋण की उपलब्धि बढ़ाने के सशर्त प्रयास किए हैं। इनमें आयरलैंड और जापान को छोड़कर सभी विकसित देश भी शामिल हैं।

अलबत्ता कुछ देशों ने औरतों के खिलाफ आर्थिक भेदभाव को गैर कानूनी करार देते हुए भी कुछ पुरानी सामाजिक प्रथाओं को बचाया है। उदाहरण के लिए कीन्या के संविधान में समान हक के प्रावधानों में संपत्ति की विरासत को छोड़ दिया गया है। कुछ इस्लामिक देशों में लड़कियों को लड़कों से आधा हिस्सा मिलता है। अन्य देशों में भी इसी प्रकार की पुरानी प्रथाओं के कारण औरतों द्वारा संपत्ति की मिल्कियत, प्रबंधन और विक्रय के हक को सीमित कर दिया गया है।

अधिकांश रूढ़िवादी मुस्लिम देशों में औरतों की आर्थिक बराबरी न्यूनतम है। इन देशों में औरत के रोजगार के लिए पति की अनुमति जरूरी है, और औरत यदि कोई व्यवसाय करना चाहे तो भी पति द्वारा अधिकृत होना चाहिए।

सर्वाधिक आर्थिक बराबरी उत्तरी यूरोप में है, जहां दूरगामी कानूनी सुधार हुए हैं और आम तौर पर लागू भी किए जाते हैं। बहरहाल, किसी भी देश का स्कोर अच्छा नहीं है। अर्थशास्त्रियों के आंकड़ों के अनुसार आर्थिक भेदभाव मिटाने के संतोषजनक प्रयास 43 देशों में हुए हैं, हालांकि व्यवधान रहा है। किसी भी देश में औरतों को बिना शर्त आर्थिक बराबरी हासिल नहीं थी।

सामाजिक समता

स्कोर	देश
18.5	फिनलैंड, स्वीडन
16.5	ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रीया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्यूबा, चेकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, पू. जर्मनी, प. जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, जमैका, नीदरलैंड, न्यूज़ीलैंड, नार्वे, पोलैंड, संयुक्त राज्य, सोवियत संघ, यूगोस्लाविया
14.5	बारबेदोस, कोस्ता, रिका, एक्वादोर, एल सल्वादोर, फ्रांस, ईराक, इटली, मेक्सिको, निकारागुआ, पुर्तगाल, रुमानिया, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, त्रिनीदाद एंड तोबागो, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, वेनेसुएला
12.5	आल्जीरिया, बेनिन, कैमरून, चीन, कोलंबिया, दोमिनिकन रिपब्लिक, गुआना, होन्दूरस, हाँग काँग, इज़राइल, जापान, पनामा, फिलिपीन्स, श्रीलंका, उरुगए
10.5	आर्जेन्तीना, बोलिविया, बोत्स्वाना, गुआतेमाला, भारत, जॉर्डन, कीन्या, द. कोरिया, मलावी, मलेशिया, नेपाल, पारागुए, पेरु, सिंगापुर, तुनीसिया, ज़ाम्बिया, ज़िम्बाब्वे
8.0	अफगानिस्तान, हैती, इंदोनेशिया, आयरलैंड, लेसोतो, लाईबीरिया, माली, मोज़ाम्बीक, सेनेगाल, सिरिया, ताइवान, तन्ज़ानिया, थाइलैंड, उ. यमन
6.0	ब्रासील, चीले, मिस्र, लिबिया, मोरॉको, नाईजीरिया, द. अफ्रीका, सूदान
4.0	बंगलादेश, कुवैत
2.0	पाकिस्तान, सउदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात

विवाह और परिवार में बराबरी

अधिकांश पश्चिमी औद्योगिक देशों में 18 साल से ऊपर की औरतें यह निर्णय करने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र हैं कि वे कब और किससे शादी करें। उन्हें तलाक की पहल करने का भी पुरुषों के बराबर हक है। जब तलाक या अलगाव हो जाता है तो बच्चा सौंपने में कानून मां का पक्ष लेता है और बच्चे के लिए वित्तीय समर्थन की मांग के जरिए या पारिवारिक संपत्ति का उचित प्रबंध करने का प्रयास करके, औरत को एक हद तक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। अध्ययन में शामिल देशों में से 22 इस समूह में रखे जा सकते है

जिनमें आस्ट्रेलिया, कनाडा, क्यूबा, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी, जमैका, नार्वे, संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ सम्मिलित हैं।

अलबत्ता ऐसी कानूनी सुरक्षा से विवाहित औरतों को समानता या सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं मिलती, जैसा कि पश्चिमी देशों में शारीरिक रूप से प्रताड़ित पत्नियों की संख्या से और आर्थिक रूप से बेसहारा विस्थापितों की संख्या से जाहिर है। परंतु फिर भी ये कई एशियाई, मध्यपूर्वी, अफ्रीकन और लातिनी अमरीकी देशों की स्थिति से स्पष्टतः अलग हैं। उदाहरण के लिए ब्राजील में पिटाई की शिकार पत्नियों के सामने कोई कानूनी रास्ता नहीं है और जो पति "अपने सम्मान की रक्षा" के लिए पत्नी की हत्या करता है वह अभयदान से आश्वस्त होता है। अधिकांश लातिनी अमेरीका में कई औरतें कानूनी विवाह की बजाए परस्पर सहमति से साथ रहती हैं और साझा संपत्ति व आर्थिक सहारे को लेकर उनके हक काफी ढुलमुल हैं।

सर्वाधिक रूढ़िवादी मुस्लिम देशों में जहां वैवाहिक बराबरी का स्कोर न्यूनतम है, वहां औरत कानूनी नजर से एक स्वायत्त या स्वतंत्र व्यक्ति ही नहीं है और उसके लिए एक नामजद पुरुष अभिभावक का होना जरूरी है आमतौर पर पिता, भाई या पति। मुस्लिम देशों में बहुपत्नी प्रथा की अनुमति है, हालांकि आर्थिक कारणों से यह प्रथा कम हो रही है। इस्लाम की रूढ़िवादी व्याख्या में औरतें सामान्यतः तलाक की पहल नहीं करतीं और मर्द जब मर्जी हो तलाक दे देते हैं और हमेशा बच्चे उन्हीं को सौंपे जाते हैं।

अधिकांश लातिनी अमरीकी देशों की तरह ही कई अफ्रीकी और एशियाई देशों, जिसमें कई नरमपंथी मुस्लिम देश शामिल हैं, ने पारिवारिक कानून को आधुनिक बनाने की कोशिश की है। जहां औरतों को उनके कानूनी हक समझाने और कानूनी सलाह उपलब्ध कराने के संगठित प्रयास हुए हैं उन जगहों को छोड़कर शेष जगहों पर इसका कोई असर परंपरागत रूढ़ियों पर नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए सन् 1978 में भारत में औरतों की विवाह आयु बढ़ाकर 18 साल कर दी गई ताकि बहुत कम उम्र की लड़कियों की शादी को रोका जा सके। दहेज को खासतौर से गैर कानूनी करार दे दिया गया है। परंतु ग्रामीण लड़कियों की शादी अभी भी 14 साल या इससे भी कम उम्र में कर दी जाती है। अखबारी रपटें बताती हैं कि दहेज को लेकर बहुओं को जलाने की घटनाएं जारी हैं।

कई अफ्रीकी देशों में औरतों के वकील भगशिश्न काटना और अन्य जननांग आपरेशनों के खिलाफ मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं। इस प्रथा के कई हिमायतियों का विश्वास है कि यह परंपरा अन्य कारणों के अलावा, औरत को पवित्र और वफादार बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ज्यादा रूढ़िवादी इलाकों में इन आपरेशनों के बगैर औरत शादी योग्य नहीं समझी जाती।

अफ्रीका, एशिया और मध्य पूर्व के इन देशों में से कई में विवाह में औरत की गैरबराबरी के कारण उनका इस बात पर कोई स्वतंत्र नियंत्रण नहीं होता कि वे कब गर्भवती होंगी या कितने बच्चे जनेंगी। उदाहरण के

जन्म प्रति औरत और औरतों की स्थिति की तुलना

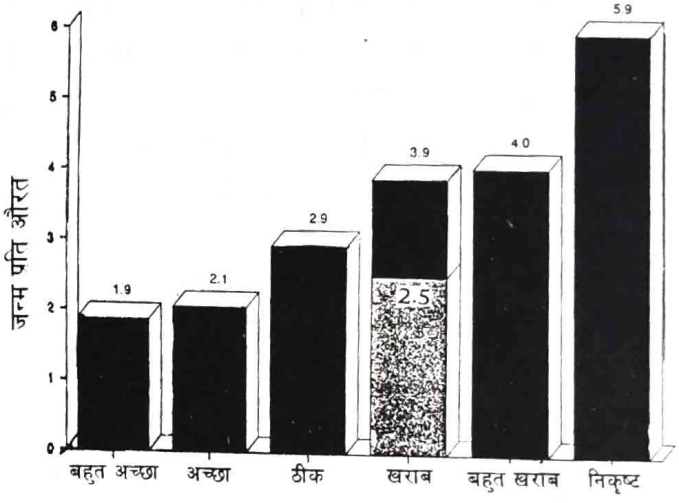

जन्म प्रति औरतः प्रति औरत औसतन बच्चे (कुल उर्वरता दर)

* चीन को शामिल करने से इस श्रेणी का कुल औसत घटता है। चीन दुनिया का सबसे अधिक आबादीवाला देश है। यहां लगभग 50 करोड़ औरतें हैं जिनकी उर्वरता दर (2.1 जन्म प्रति औरत) बहुत कम है। यदि चीन को इस श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है तब औसत जन्म प्रति औरत का आंकड़ा बढ़ेगा। यह बढ़ौतरी छायेदार हिस्से में दर्शाई गई है।

लिए, पति की अनुमति के बिना वे गर्भनिरोधक इस्तेमाल नहीं कर सकतीं। बच्चे जनने पर नियंत्रण में असमर्थता के कारण औरतों की निर्भरता बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि, उन देशों में भी जहां बच्चों को सहारा देने संबंधी कानून हैं, कई तलाकशुदा या छोड़ी गई औरतों को अपने भूतपूर्व पति से कोई पैसा नहीं मिलता।

कुछ मामलों में समता के नए कानूनी प्रावधान बनाने और लागू करने के सरकारी प्रयासों से औरतों की स्थिति बेहतर हुई है। परंतु अधिकांश समाजों में अंतर्निहित गैर बराबरी और उनके पीछे छिपी प्रवृत्तियां मुश्किल से खत्म होती हैं।

दृष्टिकोण

समान दर्जे के लिए औरतों का संघर्ष दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग रूप अख्तियार करता है। परंतु मूल रूप में एक देश की औरतों की आकांक्षाएं किसी भी अन्य देश से भिन्न नहीं हैः कानून के तहत बराबरी, बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा, बच्चा जनने पर नियंत्रण और व्यक्तिगत संभावनाओं की खोज के लिए पूरे अवसर।

औरतों को मदद करने के लिए सरकारी और अन्य हस्तक्षेपों में ये बुनियादी आकांक्षाएं इस प्रकार उभरती हैंः वास्तविक संपत्ति पर औरत के नियंत्रण हेतु कानूनी सुधार, सुरक्षित शिशुजन्म और असरदार जन्मनियंत्रण की निर्बाध उपलब्धि, शिक्षा और प्रशिक्षण, खासकर माध्यमिक और व्यवसायिक प्रशिक्षण में समान अवसर, नौकरियों में विस्तृत दायरे के जरिए इन हुनरों का इस्तेमाल करने के अवसर, वित्तीय कर्ज की उपलब्धि और कुछ ऐसे उपाय जिनसे उनका काम दोहरा बोझ कम हो। तभी औरतें अपना आधा आसमान उठाए रख पाएंगी, जैसी कि चीनी कहावत है।

आंकड़े

महिलाओं की स्थिति बेहतर बनाने के लिए यह ज़रूरी है कि विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध हो।

राष्ट्रसंघ महिला दशक उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए 1985 में आयोजित विश्व सम्मेलन की रपट में कहा गया है कि लिंग विशिष्ट पर्याप्त आंकड़े एकत्र करने के लिए और अधिक छानबीन की आवश्यकता है।

महिलाओं की स्थिति के अनुसार देशों को क्रमबद्ध करने के लिए आंकड़े एकत्रित करने में कई समस्याएं आईं। हालांकि इस अध्ययन में शामिल किए गए देशों में विश्व की 92 प्रतिशत महिलाएं रहती हैं, फिर भी कई देशों को इस अध्ययन में से छोड़ देना पड़ा क्योंकि उनसे कई महत्वपूर्ण सूचकों के बारे में आंकड़े या तो उपलब्ध ही नहीं थे या फिर जो जानकारी उपलब्ध थी वह पुरानी थी। इन में इरान, वियतनाम, उ. कोरिया और कई अफ्रीकी देश शामिल हैं।

जिन पांच क्षेत्रों में अध्ययन किया गया उनमें प्रकाशित आंकड़ों और विश्वसनीयता में भी बहुत अंतर था। स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रजनन से संबंधित आंकड़े फिर भी पर्याप्त और ताजा थे, लेकिन महिलाओं की आर्थिक स्थिति के बारे में विश्वसनीय जानकारी की आम तौर पर कमी थी। पुरुषों के साथ महिलाओं के कानूनी और वास्तविक बराबरी के दर्जे के मूल्यांकन भी अपर्याप्त और अविश्वसनीय थे।

इन कठिनाइयों के बावजूद, महिलाओं की स्थिति के अनुसार देशों को क्रमबद्ध करने के लिए उपयोग में लाए गए 1980 सूचकों में से लगभग 85 प्रतिशत सूचक, राष्ट्रसंघ के शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को), अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) और संयुक्त राज्य अमेरिका के जनगणना विभाग के द्वारा 1980 के बाद संकलित जानकारी पर आधारित है।

अतिरिक्त मुफ्त प्रतियां सीमित संख्या में निम्नलिखित पतों पर उपलब्ध हैं:

ISSN 0197-2235 BP-20
Population Crisis Committee
1120 19th Street, N W
Washington, D C 20036 (USA)

किशोर भारती
बनखेड़ी
होशंगाबाद जिला
म.प्र-461 990